

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली, 30 मई, 2023 दैनिक जागरण DATED

भलस्वा झील की हालत में दिखने लगा सुधार

पांच दिन पूर्व झील का निरीक्षण करने पहुंचे थे उपराज्यपाल जल मंत्री ने लगाया था श्रेय लेने का आरोप

जागरण पड़ताल

शिषा सुमन • बाहरी दिल्ली

भलस्वा झील की स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार आया है, लेकिन इसमें डीडीए का प्रयास ज्यादा और जल बोर्ड का अपेक्षाकृत कम नजर आता है। यह भी कहा जाता है कि पहली बार पिछले वर्ष अक्टूबर में एलजी द्वारा झील का दौरा करने के बाद से सुधार कार्य में ज्यादा तेजी आई। उसके बाद 23 मई को जब एलजी इस झील का दौरा पर आए तो उन्होंने यहां हुए काम पर संतोष जताते हुए डीडीए के प्रयासों को सराहा था। लेकिन, जल मंत्री सौरभ भारद्वाज को यह नागवार गुजरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप सरकार के नेतृत्व में यह कार्य जल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। एलजी इस कार्य का अनुचित श्रेय न लें। इस पर जागरण टीम ने झील का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत कर सच जानने का प्रयास किया।

मौजूदा समय में यहां डीडीए की तरफ से झील के चारों ओर इसके किनारों को बेहतर बनाने का काम 80 से 90 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है। डीडीए ही इसकी साफ-सफाई भी करा रहा है। इसके लिए डीडीए ने एक निजी कंपनी से डेढ़



भलस्वा झील के किनारे बनाई जा रही दीवार • जागरण

वर्ष का अनुबंध किया है। साथ ही बैक्टिरिया डोजिंग का कार्य भी चल रहा है, ताकि गोबर से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। झील में प्लास्टिक सहित अन्य प्रकार की गंदगी भी साफ की जा रही है। वहीं, नगर निगम की जिम्मेदारी झील के बाहरी क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने की है, ताकि कचरा झील तक न पहुंच पाए। डीडीए द्वारा यहां पर रेनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) भी बनाया जा रहा है, जिसका 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

इससे पहले जल बोर्ड द्वारा भलस्वा डेरी की तरफ एक वैकल्पिक ड्रेन

बनाई गई थी, ताकि गंदा पानी और गोबर झील में न जा सके।

वर्ष 2021 के नवंबर में इस कार्य की शुरुआत हुई थी, जो 2022 के अंत तक चला, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। इसके बने जाने के बाद भी झील में बहने वाली गंदगी में कमी नहीं आई। जल बोर्ड की प्लानिंग सही न होने से यह कारगर नहीं हो सकी। ड्रेन बनने के बाद भी डेरी क्षेत्र से बहने वाला दूषित पानी जमा हो रहा है।

जानकारी के अनुसार यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत बनाए गए इंटरनल सर्कुलेशन रिएक्टर



भलस्वा झील के किनारे पड़ा कूड़ा व गंदगी • जागरण

(आइसी) डेरी के स्तर से छह से आठ मीटर तक नीचे है। इससे पानी का बहाव सही तरह से नहीं हो पाता है। ड्रेन बनाने में लगभग आठ लाख रुपये खर्च हुए हैं।

मुकुंदपुर में पहले से आइसी बनी हुई थी और इसी तरह की भलस्वा डेरी में भी बनी है। एनजीटी की गाइडलाइन के हिसाब से इसमें किसी भी प्रकार का दूषित पानी नहीं गिरना चाहिए और इसके जरिये दूषित पानी को रोककर रखा जाए और उसे स्वच्छ कर भेजा जाए। लेकिन, ट्रीटमेंट प्लांट के तहत ड्रेन के आउट प्वाइंट को ऊपर रख दिया।

झील में गंदा पानी गिरने से रोका गया : जल बोर्ड

जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि एक बड़ी समस्या यह थी कि भलस्वा झील में पहले गोबर युक्त पानी गिर रहा था। इससे झील में प्रदूषण बढ़ रहा था और इसे बचाने के लिए जरूरी था कि झील में गोबर या सीवरेज युक्त गंदा पानी न गिरने पाए। जल बोर्ड ने इसकी योजना तैयार कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया। इससे भलस्वा झील में अब गंदा पानी गिरना बंद हो गया है। यह झील के पुनर्विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम था।

पानी की सफाई के साथ गाद भी निकाल रहे

डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि डीडीए की तरफ से न केवल झील के पानी को साफ किया जा रहा है, बल्कि उससे गंदगी भी निकाली जा रही है। झील के किनारों को भी साफ कर बेहतर बनाया जा रहा है। यहां आने वालों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए झील के आसपास पक्का भी किया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | मंगलवार, 30 मई 2023

DATED-- नई दिल्ली, 30 मई, 2023

दिल्ली में फिर लौट सकता है सीलिंग की कार्रवाई का दौर!

मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्यों ने SC में दायर की रिपोर्ट

Sudama.Yadav@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : कमर्शल व रिहायशी इलाकों में सीलिंग से लंबे समय तक राहत के बाद फिर सीलिंग का दौर लौट सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई मॉनिटरिंग कमिटी के तीन सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर की है और मांग की है कि जिन प्रॉपर्टी को उनके निर्देश पर बीते कुछ सालों में सील किया गया है, उनका मौके पर जांच की मंजूरी दी जाए। इसके अलावा रिहायशी या कमर्शल इलाकों में जो नए अवैध निर्माण किए गए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की है। कमिटी के सदस्यों ने इसके लिए एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए व बाकी एजेंसियों को भी पत्र लिखा है। हालांकि अभी लोकल एजेंसियों ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया है।

कमिटी के सदस्यों ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि उन्हें कई लोगों ने अलग अलग रिहायशी इलाकों में भारी पैमाने पर अवैध निर्माण और स्टिल्ट पार्किंग स्पेस का मिस यूज करने की शिकायत की है। कमिटी ने मुरादी रोड और बाटला हाउस एरिया का उदाहरण दिया है, जहां पिछले कई महीनों से अवैध निर्माण बेलगाम हो रहा है। एमसीडी के जिन अफसरों पर इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है, वह कुछ नहीं कर रहे। अवैध निर्माणों के खिलाफ



जांच करने के लिए कहा

- जिन लोगों ने सील टेंपर्ड किया है, उनके खिलाफ हो सकती है कार्रवाई
- सदस्यों ने सील की गई प्रॉपर्टी की मौके पर जांच करने के लिए भी कहा

कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों को कमिटी ने पत्र भी लिखा, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

243 प्रॉपर्टी की सील टेंपर्ड पाई गई

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल एमसीडी कमिशनर को आदेश

दिया गया कि कमिटी के आदेश जितने भी प्रॉपर्टी सील या डी-सील किए गए, उनकी पूरी रिपोर्ट दें। कमिशनर ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें 243 प्रॉपर्टी की सील टेंपर्ड पाई गई। एमसीडी अफसरों ने कुल 3998 प्रॉपर्टी की रिपोर्ट उपलब्ध कराई, जिसमें से 2577 ऐसी थीं, जिनके बेसमेंट में स्टिल्ट पार्किंग की जगह दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन मिले। इसलिए बेसमेंट में बने अन्य तरह के प्रॉपर्टी को सील किया गया था। एनडीएमसी एरिया में कमिटी के निर्देश पर 81 प्रॉपर्टी सील किए गए थे। एनडीएमसी अधिकारियों ने इनकी मौके पर जांच की तो सभी सील मिले, लेकिन जोरबाग और बंगाली मार्केट में 14 ऐसे प्रॉपर्टी पाई गई हैं, जिसमें मिस यूज की शिकायत है।

शांति वन लालबती के पास हटवाया अतिक्रमण



शांति वन लाल बती के पास अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया • जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए ने कार्रवाई कर करीब दो एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। सोमवार को पुलिस और प्रशासन के सहयोग से डीडीए ने मध्य दिल्ली क्षेत्र में शांति वन लालबती के पास यह कार्रवाई की। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। डीडीए की जमीन पर वर्षों से कब्जा था। यहीं जगन्नाथ मंदिर भी है। इस कार्रवाई में कई घरों और

दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में दिनभर कार्रवाई चली। इस मौके पर मध्य दिल्ली क्षेत्र के एसडीएम अरविंद राणा ने बताया कि अतिक्रमण के इस लिए एसटीएफ बना दी गई और डीडीए की देखरेख में यह कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से तय किया गया है कि जो लोग बेघर हुए हैं या जरूरतमंद हैं, उन्हें रैनबसेरे में रखा जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: दैनिक जागरण नई दिल्ली, 30 मई, 2023 ---DATED---

सोसायटी के पदाधिकारियों ने प्रकृति से खिलवाड़ न करने की ली शपथ



● चिराग दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय में हुआ जागरण जल संवाद कार्यक्रम

● जल संरक्षण के मुद्दे पर सोसायटियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षदों ने लिया भाग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: चिराग दिल्ली स्थित चिराग दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय में विभिन्न सोसायटी के अध्यक्षों ने जागरण जल संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें चिराग दिल्ली, शेख सराय और पंचशील एनक्लेव के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पहुंचे। सभी ने सोसायटी में जल संरक्षण के मुद्दे पर जोर दिया। वहीं चिराग दिल्ली के पूर्व पार्षद राकेश गुलिया ने जल संचयन की व्यवस्था को बढ़ाने पर जोर दिया।

इस दौरान चिराग दिल्ली गांव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुरेश सहरावत ने कहा कि प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो पानी जमीन में कैसे जाएगा। उन्होंने डीडीए के आकड़ों के हवाले से बताया कि पूरी दिल्ली में कुल 35 वाटर बाडी है और 36 रेन हार्वेस्टिंग बाडी है। उन्होंने कहा कि पहले के कई वाटर बाडी देखरेख के अभाव में आज सूख चुके हैं। वहीं चिराग दिल्ली में सिर्फ एक जल संचयन की व्यवस्था थी जो अब खराब पड़ी



जल जागरण अभियान के तहत जल संवाद कार्यक्रम में पहुंचे चिराग दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग ● जागरण

है। पहले यहां का वाटर लेवल 65 और 80 फीट के बीच था, लेकिन आज यही वाटर लेवल 350 फीट के करीब पहुंच गया है। चिराग दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि जल संचयन की व्यवस्था न होने का एक बड़ा कारण यह है कि दिल्ली जल बोर्ड आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि शेख सराय में तो बिना मोटर के भी पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन चिराग दिल्ली में कहीं पानी एक टाइम आ रहा है तो कहीं एक भी टाइम नहीं। वहीं जल

संरक्षण पर सुझाव देते हुए मुकेश शर्मा ने कहा कि यहां पानी की सप्लाई सुबह चार बजे से सात बजे के बीच होती है। ऐसे में कई घर में चार बजे मोटर चालू कर दी जाती है और पानी भरकर गिरता रहता है। यदि यहां पानी सप्लाई की टाइमिंग सही होगी तो काफी हद तक जल संरक्षित हो सकेगा। वहीं पूर्व पार्षद राकेश गुलिया ने कहा कि दिल्ली समेत दक्षिणी दिल्ली का ग्राउंड वाटर काफी नीचे जा रहा है। इस कारण द्यूब वेल को बंद कर दिया गया था। यहां भी पार्कों में लगे सभी द्यूब वेल को बंद कर दिया गया।

पार्कों में वर्षा जल संग्रहण के लिए रिचार्ज पिट बनाएगा जल बोर्ड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: वर्षा जल संग्रहण के जरिये भूजल स्तर बढ़ाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पार्कों में रिचार्ज पिट बनाएगा।

जल संरक्षण

साथ ही भूजल स्तर बढ़ाने पर पानी आपूर्ति बढ़ाने के लिए डीडीए के पार्कों में द्यूबवेल भी लगाने पर जल बोर्ड विचार कर रहा है। इस संदर्भ में जल बोर्ड को एक्शन प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिया

गया है। सोमवार को पानी से जुड़े मामले पर छतरपुर, सीलमपुर व गोकलपुरी क्षेत्र के विधायकों व जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति की वितरण व्यवस्था में सुधार लिए पानी की आडिट योजना के तहत सभी जल शोधन संयंत्रों, भूमिगत जलाशयों व पाइप लाइनों पर जगह-जगह फ्लो मीटर लगाए जा रहे हैं। कई इलाकों में फ्लो मीटर लगाने का काम पूरा हो चुका है।

- जल बोर्ड को एक्शन प्लान तैयार करने के लिए निर्देश
- दिल्ली विकास प्राधिकरण के करीब 700 पार्क हैं राजधानी में

फ्लो मीटर को स्काडा साफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। इससे पानी आपूर्ति की आनलाइन निगरानी हो सकेगी और पानी आपूर्ति की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे यह पता चल सकेगा कि जल शोधन संयंत्रों से जितना पानी शोधन के बाद भूमिगत जलाशयों में छोड़ा जा रहा है, उतना पूरा

पानी पाइप लाइन से लोगों के घरों में पहुंच पा रहा है या नहीं। साथ ही इससे यह पता चल सकेगा कि पानी की कितनी बर्बादी और चोरी हो रही है। इससे पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने जल बोर्ड के अधिकारियों को गोकलपुरी व सीलमपुर सहित बाकी बचे सभी इलाकों में फ्लो मीटर लगाने का काम समय से पूरा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल बोर्ड करीब 500 नए द्यूबवेल लगाने की योजना पर काम कर रहा है।

जल बोर्ड इस योजना को विस्तार देने की तैयारी में है। इसी क्रम में डीडीए के पार्कों में रिचार्ज पिट व द्यूबवेल लगा जल बोर्ड पानी आपूर्ति बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जल्द ही जल बोर्ड इस मामले पर डीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, ताकि योजना तैयार कर अमल किया जा सके। डीडीए के करीब 700 पार्क हैं। जल बोर्ड को उम्मीद है कि उन पार्कों में वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देकर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। इससे द्यूबवेल के जरिये पेयजल आपूर्ति भी बढ़ सकती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला

PERS

नई दिल्ली। मंगलवार • 30 मई • 2023

राष्ट्रीय
सहारा

पानी का डाटा होगा
ऑनलाइन, आपूर्ति की
होगी डिजिटल निगरानी

नई दिल्ली। राजधानी में घर-घर सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पेयजल उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर भी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) जल वितरण की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वाटर ऑडिट की योजना के तहत सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, प्राइमरी एवम सेकेंडरी यूजीआर और टैपिंग पर फ्लो मीटर लगा रहा है। इसके साथ ही पानी का उत्पादन और भूजल में वृद्धि करने के लिए डीजेबी डीडीए के पार्को में रिचार्ज पिट और ट्यूबवेल्स लगाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए डीजेबी के अधिकारियों को एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में फ्लो मीटर लगाने का काम पूरा हो चुका है और कई जगहों में फ्लो मीटर लगाने का काम जारी है। फ्लो मीटर्स को सॉफ्टवेयर से जोड़ कर पानी के डाटा को ऑनलाइन किया जा रहा है। डाटा ऑनलाइन होने से कहीं भी पानी का डाटा देखा जा सकता है और इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। ब्यूरो

वाटर ऑडिट से पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में होगा बड़ा सुधार

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली जल बोर्ड जल वितरण की व्यवस्था में सुधार करने के लिए वाटर ऑडिट की योजना के तहत सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, प्राइमरी एवम सेकेंडरी यूजीआर और टैपिंग पर फ्लो मीटर लगा रहा है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में फ्लो मीटर लगाने का काम पूरा हो चुका है और बाकी

विधानसभाओं में फ्लो मीटर लगाने का काम जारी है। फ्लो मीटर का डाटा ऑनलाइन होने से कहीं भी पानी का डाटा देखा जा सकता है और इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि पानी का उत्पादन और भूजल में वृद्धि करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड डीडीए के पार्को में रिचार्ज पिट और

ट्यूबवेल्स लगाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए अधिकारियों को एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने सोमवार को जल बोर्ड मुख्यालय में छत्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक करतार सिंह तंवर, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अब्दुल रहमान और गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार के साथ बैठक की। इसमें दिजबो के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

जल बोर्ड न सिर्फ पानी का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है बल्कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जल वितरण को भी बेहतर करने में लगा है। फ्लो मीटर लगने के बाद पता चल पाएगा कि क्या लोगों को घरों में भी उतनी ही मात्रा में पानी की आपूर्ति हो रही है, जितनी मात्रा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी सप्लाई किया जा रहा है।

सीएम के निर्देश पर
फ्लो मीटर लगाने का
काम जारी

दिल्ली जल बोर्ड डीडीए
के पार्को में रिचार्ज पिट
और ट्यूबवेल्स लगाने
पर कर रहा विचार